Lakshya IAS academy

24 Aug 2026

DAILY CURRENT AFFAIRS

Mr. R.P. Singh Sir
(MD)

लक्ष्य IAS तेलीबाग लखनऊ
Lakshya IAS Academy
8182093320

1. मोबाइल फोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने 62,500 करोड़ रुपये की योजना शुरू की

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परिवेश को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना शुरू की है। यह योजना मोबाइल विनिर्माताओं और भारतीय ब्रांडों को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिसमें प्रमुख घटकों की घरेलू खरीद के लिए 1.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल है। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना, भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना, लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना और लगभग 39 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन उत्पादन को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु:

- 62,500 करोड़ रुपये की मोबाइल फोन विनिर्माण योजना 1 अप्रैल, 2026 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए चलेगी, जिसका उद्देश्य मोबाइल फोन विनिर्माण का विस्तार करना और भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देना है।
- यह योजना कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले असेंबली, मैकेनिकल पार्ट्स और बैटरी सेल जैसे प्रमुख घटकों की घरेलू खरीद के लिए 1.5 प्रतिशत तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- इस योजना से नीति अवधि के दौरान लगभग 39 लाख करोड़ रुपये के संचयी मोबाइल फोन उत्पादन और लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

1. Centre Launches Rs. 62,500 Crore Scheme to Boost Mobile Phone Manufacturing

The Centre has launched the Rs. 62,500-crore Mobile Phone Manufacturing Scheme (MPMS) for five years, from 2026-27 to 2030-31, to strengthen India's electronics manufacturing ecosystem. The scheme will provide production-linked incentives to mobile manufacturers and Indian brands, with an additional incentive of up to 1.5% for domestic sourcing of key components. It aims to boost domestic value addition, strengthen supply chains, support Indian brands, generate around 60,000 direct jobs, and drive mobile phone production worth approximately Rs. 39 lakh crore.

Key points:

- The Rs. 62,500-crore MPMS will run for five years from April 1, 2026, to FY 2030–31, with incentives aimed at expanding mobile phone manufacturing and promoting Indian brands.
- The scheme offers an additional incentive of up to 1.5% for domestic sourcing of key components such as camera modules, display assemblies, mechanical parts, and battery cells.
- MPMS is expected to generate around Rs. 39 lakh crore in cumulative mobile phone production and create approximately 60,000 direct jobs during the policy period.

2. सोफी एडेनोट ने अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बनकर इतिहास रचा

18 अगस्त, 2026 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष यात्री सोफी एडेनोट अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला और बाह्य अंतरिक्ष गतिविधि करने वाली दूसरी यूरोपीय महिला बनीं। छह घंटे और 23 मिनट तक चले इस अभियान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के जेड1 ट्रस पर एक खराब स्पेस-टू-ग्राउंड एंटीना को बदलना शामिल था। सोफी एडेनोट और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को बोल्ट और तारों के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अभियान नियंत्रण कक्ष ने इसके स्थान पर पुराने एंटीना को ही सुरक्षित करने का निर्देश दिया। इस ऐतिहासिक बाह्य अंतरिक्ष गतिविधि ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में फ्रांस और यूरोप की बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया।

मुख्य बिंदुः

- सोफी एडेनोट अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला और दूसरी यूरोपीय महिला बनीं, जिन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 6 घंटे और 23 मिनट की बाह्य अंतरिक्ष गतिविधि पूरी की।
- बाह्य अंतरिक्ष गतिविधि संख्या 97 का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के जेड1 ट्रस पर खराब पड़े स्पेस-टू-ग्राउंड एंटीना को बदलना था, हालांकि बोल्ट और तारों के साथ आने वाली समस्याओं के कारण इसे पूरी तरह से स्थापित नहीं किया जा सका।
- यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और रखरखाव के इतिहास में 282वीं अंतरिक्ष चहलकदमी थी, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष अन्वेषण में यूरोप की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

2. Sophie Adenot Makes History as First French Woman to Conduct a Spacewalk

On August 18, 2026, ESA astronaut Sophie Adenot became the first French woman to perform a spacewalk and the second European woman to conduct an EVA. Lasting six hours and 23 minutes, the mission involved replacing a faulty Space-to-Ground Antenna on the ISS's Z1 truss. Adenot and NASA astronaut Anil Menon encountered difficulties with bolts and cables, prompting Mission Control to secure the old antenna instead. The historic EVA highlighted France and Europe's growing role in human space exploration.

Key points:

- Sophie Adenot became the first French woman and the second European woman to conduct a spacewalk, completing a 6-hour-23-minute EVA outside the ISS with NASA astronaut Anil Menon.
- The main objective of EVA-97 was to replace the malfunctioning Space-to-Ground Antenna (SGANT) on the ISS's Z1 truss, although installation issues with bolts and cables prevented its full completion.
- The mission marked the 282nd spacewalk in the history of ISS construction and servicing, highlighting Europe's growing role in human spaceflight and space exploration.

3. सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य वकालत अभ्यास की अवधि घटाई

- सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए अनिवार्य कानूनी वकालत अभ्यास की आवश्यकता को तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने भर्ती प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण और एक वर्ष की निगरानीयुक्त क्लर्कशिप की व्यवस्था शुरू की है। 20 मई, 2025 से 31 मार्च, 2027 के बीच जारी की गई न्यायिक परीक्षा अधिसूचनाओं के तहत आने वाले अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत भी प्रदान की गई है। इस अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष तक प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

मुख्य बिंदुः

- सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य कानूनी वकालत अभ्यास की आवश्यकता को तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया है।
- संशोधित रूपरेखा में एक वर्ष का प्रशिक्षण और एक वर्ष की निगरानीयुक्त क्लर्कशिप शामिल है, जिसमें समग्र भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन तीन वर्षों में किया जाएगा।
- अंतरिम राहत के रूप में, 20 मई, 2025 और 31 मार्च, 2027 के बीच जारी न्यायिक परीक्षा अधिसूचनाओं के दायरे में आने वाले अभ्यर्थी पूर्व की तीन वर्षीय अभ्यास आवश्यकता को पूरा किए बिना भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

3. Supreme Court Cuts Mandatory Practice Requirement for Judicial Service Aspirants

- The Supreme Court has reduced the mandatory legal practice requirement for entry-level judicial service examinations from three years to one year. A three-judge bench led by CJI Surya Kant introduced one year of training and one year of supervised clerkship as part of the recruitment process. Transitional relief has also been granted to candidates covered by judicial examination notifications issued between May 20, 2025, and March 31, 2027. Selected candidates during this period will serve as trainee judicial officers for one year.

Key points:

- The Supreme Court has reduced the mandatory legal practice requirement from three years to one year for candidates appearing in entry-level judicial service examinations.
- The revised framework includes one year of training and one year of supervised clerkship, with the overall recruitment and training process to be assessed over three years.
- As transitional relief, candidates covered by judicial examination notifications issued between May 20, 2025, and March 31, 2027, can appear without completing the earlier three-year practice requirement.

4. पश्चिम बंगाल ने जबरन वसूली से निपटने के लिए चार टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किए

पश्चिम बंगाल ने नागरिकों को अवैध गतिविधियों की सीधे रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए चार टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। ये समर्पित नंबर जबरन वसूली (155334), सिंडिकेट गतिविधियों (155335), अवैध सड़क और टोल टैक्स वसूली (155337), तथा अवैध शराब (155339) से संबंधित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के अपने दौरे के दौरान इन हेल्पलाइनों के कामकाज की समीक्षा की और आश्वासन दिया कि इनके माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों और अधिकारियों के बीच संचार को मजबूत करना और गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदुः

- पश्चिम बंगाल ने जबरन वसूली, सिंडिकेट गतिविधियों, अवैध सड़क अथवा टोल टैक्स वसूली और अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों के लिए चार टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की हैं।
- हेल्पलाइन नंबर हैंः जबरन वसूली के लिए 155334, सिंडिकेट गतिविधियों के लिए 155335, अवैध सड़क और टोल टैक्स वसूली के लिए 155337, और अवैध शराब के लिए 155339।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अपने दौरे के दौरान हेल्पलाइनों की समीक्षा की और इन समर्पित माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

4. West Bengal Introduces Four Toll-Free Helplines to Combat Extortion

West Bengal has launched four toll-free helpline numbers to enable citizens to report illegal activities directly. The dedicated numbers address extortion (155334), syndicate activities (155335), illegal road and toll tax collection (155337), and illegal liquor (155339). Union Home Minister Amit Shah reviewed the functioning of these helplines during his visit to the state and assured that complaints received through them would be acted upon swiftly. The initiative aims to strengthen communication between citizens and authorities and ensure prompt action against unlawful activities.

Key points:

- West Bengal has launched four toll-free helplines to enable citizens to report extortion, syndicate activities, illegal road/toll tax collection, and illegal liquor-related activities.
- The helpline numbers are 155334 for extortion, 155335 for syndicate activities, 155337 for illegal road and toll tax collection, and 155339 for illegal liquor.
- Union Home Minister Amit Shah reviewed the helplines during his visit to West Bengal and assured swift action on complaints received through these dedicated channels.

5. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले डिकॉय की तकनीक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हस्तांतरित की

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी उत्पादन के लिए सबमरीन-फायर्ड डिकॉय की तकनीक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है। इस समझौते पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा हस्ताक्षर किए गए। सबमरीन-फायर्ड डिकॉय एक रक्षात्मक प्रणाली है जिसे भ्रामक सिग्नल और संकेत उत्पन्न करके पनडुब्बियों को आने वाले टॉरपीडो से बचाने के लिए तैयार किया गया है। इसका घरेलू उत्पादन भारत की पानी के भीतर की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करेगा और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करेगा।

मुख्य बिंदु:

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला ने स्वदेशी उत्पादन के लिए सबमरीन-फायर्ड डिकॉय की तकनीक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हस्तांतरित की है।
- सबमरीन-फायर्ड डिकॉय एक जवाबी रक्षा प्रणाली है जिसे शत्रुतापूर्ण टॉरपीडो को गुमराह करने के लिए भ्रामक सिग्नल और संकेत उत्पन्न करके पनडुब्बियों की रक्षा के लिए बनाया गया है।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारत की पानी के भीतर की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता घटाएगा और आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाएगा।

5. DRDO Transfers Submarine-Launched Decoy Technology to BDL

- DRDO has transferred the technology for the Submarine-Fired Decoy (SFD) to Bharat Dynamics Limited (BDL) for indigenous production. The agreement was signed by DRDO's Naval Science and Technology Laboratory (NSTL). The SFD is a countermeasure system designed to protect submarines from incoming torpedoes by generating misleading signals and signatures. Its domestic production will strengthen India's underwater defence capabilities, reduce dependence on foreign suppliers, and support the Aatmanirbhar Bharat initiative in defence manufacturing.

Key points:

- DRDO's Naval Science and Technological Laboratory (NSTL) has transferred the technology for the Submarine-Fired Decoy (SFD) to Bharat Dynamics Limited (BDL) for indigenous production.
- The SFD is a countermeasure system designed to protect submarines from incoming torpedoes by generating deceptive signals and signatures to mislead hostile torpedoes.
- The technology transfer will strengthen India's underwater defence capabilities, reduce dependence on foreign suppliers, and support the Aatmanirbhar Bharat initiative.

6. आशुतोष परिदा को उनकी कविता के लिए सरला पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा

ओड़िया कवि और पूर्व वैज्ञानिक आशुतोष परिदा को उनके कविता संग्रह 'बिश्वास दे पृथिवी' के लिए सरला पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। इंपैक्ट संस्था द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार ओड़िया साहित्य में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है और इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र, तांबे की पट्टिका तथा 7 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार वितरण समारोह 25 अक्टूबर, 2026 को भुवनेश्वर में आयोजित होना तय है। इसके अतिरिक्त, गुरु दुर्गा चरण रणबीर और दामोदर बेहरा को कला के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए इला-बंशीधर पांडा कला सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाएगा।

मुख्य बिंदुः

- आशुतोष परिदा को उनके कविता संग्रह 'बिश्वास दे पृथिवी' के लिए सरला पुरस्कार 2026 हेतु चुना गया है। इस पुरस्कार में 7 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और तांबे की पट्टिका शामिल है।
- सरला पुरस्कार ओड़िया भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान को मान्यता प्रदान करता है और यह 25 अक्टूबर, 2026 को भुवनेश्वर में परिदा को औपचारिक रूप से प्रदान किया जाएगा।
- गुरु दुर्गा चरण रणबीर और दामोदर बेहरा को कला के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए इला-बंशीधर पांडा कला सम्मान 2026 के साथ-साथ 2.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

6. Ashutosh Parida to Be Honoured with Sarala Puraskar 2026 for His Poetry

Odia poet and former CSIR-IMMT scientist Ashutosh Parida has been selected for the Sarala Puraskar 2026 for his poetry collection Bishwas De Pruthwi. Presented by IMPaCT, the award recognises outstanding literary contributions in Odia and carries a citation, copper plaque, and Rs. 7 lakh cash prize. The award ceremony is scheduled in Bhubaneswar on October 25, 2026. Additionally, Guru Durga Charan Ranbir and Damodar Behera will receive the Ila-Bansidhar Panda Kala Samman 2026 for their lifetime contributions to the arts.

Key points:

- Ashutosh Parida has been selected for the Sarala Puraskar 2026 for his poetry collection Bishwas De Pruthwi. The award carries a Rs. 7 lakh cash prize, citation, and copper plaque.
- The Sarala Puraskar recognises outstanding literary contributions in the Odia language and will be formally presented to Parida in Bhubaneswar on October 25, 2026.
- Guru Durga Charan Ranbir and Damodar Behera will receive the Ila-Bansidhar Panda Kala Samman 2026 for their lifelong contributions to the arts, along with a Rs. 2.5 lakh cash prize each.

7. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से पूरे भारत के 48 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा

- शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे। पुरस्कार विजेताओं में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्र सरकार के संगठनों के 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। तीन-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से चयनित ये शिक्षक सरकारी स्कूल, पीएम श्री, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- 5 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 प्रदान किए जाएंगे, जिस दिन भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
- पुरस्कार पाने वालों में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्र सरकार के संगठनों के 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं, जिनका चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है।
- समारोह में पुरस्कार विजेताओं पर बनी लघु वृत्तचित्र फिल्में दिखाई जाएंगी और इसका दूरदर्शन तथा स्वयं प्रभा चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

7. National Teachers' Awards 2026 to Honour 48 Teachers Across India

- The National Teachers Awards 2026 will be presented to 48 school teachers by President Droupadi Murmu at Vigyan Bhawan, New Delhi, on 5 September 2026, coinciding with Teachers' Day. The awardees include 26 men and 22 women from 27 States, 7 Union Territories, and 6 Central Government organisations. Selected through a three-stage process, they represent institutions including government, PM SHRI, Kendriya Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sainik, and Eklavya Model Residential Schools. The ceremony will be broadcast live.

Key points:

- 48 school teachers will receive the National Teachers Awards 2026 from President Droupadi Murmu at Vigyan Bhawan, New Delhi, on September 5, 2026, which is observed as Teachers' Day in India.
- The awardees include 26 male and 22 female teachers from 27 States, 7 Union Territories, and 6 Central Government organisations, selected through district-, state-, and national-level processes.
- The ceremony will feature short documentaries on the awardees and will be broadcast live on Doordarshan and SWAYAM PRABHA channels.

8. फोनपे ने पीएम गतिशक्ति और स्टार्टअप परिवेश को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

अगस्त 2026 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा-आधारित बुनियादी ढांचा योजना का समर्थन करने के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल में फोनपे पल्सप्रो डेटा को एकीकृत करने हेतु फोनपे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फोनपे ने प्रौद्योगिकी पहुंच, मार्गदर्शन और बाजार के अवसर प्रदान करके स्टार्टअप परिवेश को सशक्त बनाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा शैल इंडिया के साथ भी साझेदारी की है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की स्थापना को मंजूरी दी, जो इसका तीसरा न्यायिक स्थान बनेगा। इस कदम का उद्देश्य न्याय तक पहुंच में सुधार करना और निवासियों के लिए यात्रा की कठिनाई को कम करना है।

मुख्य बिंदु:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा फोनपे ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल में फोनपे पल्सप्रो डेटा को एकीकृत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे अधिक डेटा-आधारित बुनियादी ढांचा योजना तैयार की जा सकेगी।
- फोनपे, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा शैल इंडिया स्टार्टअप्स को प्रौद्योगिकी तक पहुंच, परामर्श, बाजार के अवसर और उद्योग सहायता प्रदान करके स्टार्टअप परिवेश को मजबूत करने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ को मंजूरी दी, जो इसका तीसरा न्यायिक स्थान होगा और लेह तथा कारगिल के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगा।

8. PhonePe Signs MoUs with MeitY and DPIIT to Strengthen PM GatiShakti and Startup Ecosystem

In August 2026, MeitY signed an MoU with PhonePe to integrate PhonePe PulsePro data into the PM GatiShakti National Master Plan portal, supporting data-driven infrastructure planning. PhonePe also partnered with DPIIT and Shell India to strengthen the startup ecosystem through technology access, mentorship, and market opportunities. Separately, the Union Cabinet approved a permanent bench of the J&K and Ladakh High Court in Ladakh, which will become its third judicial location. The move aims to improve access to justice and reduce travel burdens for residents.

Key points:

- MeitY and PhonePe signed an MoU to integrate PhonePe PulsePro data into the PM GatiShakti National Master Plan portal, enabling more data-driven infrastructure planning.
- PhonePe, DPIIT, and Shell India are also collaborating to strengthen the startup ecosystem by providing startups with technology access, mentorship, market opportunities, and industry support.
- The Union Cabinet approved a permanent bench of the J&K and Ladakh High Court in Ladakh, which will become its third judicial location and improve access to justice for people in Leh and Kargil.

9. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना पहला 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बॉन्ड जारी करने का कार्य पूरा किया

अगस्त 2026 में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाई के माध्यम से अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड निर्गम से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए। वर्ष 2029 में परिपक्व होने वाले इन तीन वर्षीय बॉन्डों पर 5.625 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर देय है और इन्हें अमेरिका से बाहर के निवेशकों के लिए रेगुलेशन एस प्रारूप के तहत जारी किया गया था। इन बॉन्डों को एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स से स्थिर दृष्टिकोण के साथ निवेश-ग्रेड 'ट्रिपल बी माइनस' रेटिंग प्राप्त हुई। ब्लैकरॉक और कैपिटल ग्रुप सहित प्रमुख वैश्विक निवेशकों ने इस पेशकश में भाग लिया।

मुख्य बिंदु:

- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाई के माध्यम से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाए, जिससे वैश्विक ऋण पूंजी बाजार में उसका पहला प्रवेश हुआ।
- वर्ष 2029 में देय इन 3-वर्षीय बॉन्डों पर 5.625 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर और स्थिर दृष्टिकोण के साथ एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स से निवेश-ग्रेड 'ट्रिपल बी माइनस' रेटिंग प्राप्त है।
- इस बॉन्ड निर्गम ने ब्लैकरॉक, कैपिटल ग्रुप और अलायंसबर्नस्टीन सहित प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों को आकर्षित किया, जिनका ब्याज भुगतान अर्धवार्षिक रूप से निर्धारित है।

9. IDFC FIRST Bank Completes Its Maiden USD 500 Million Bond Issuance

In August 2026, IDFC First Bank raised USD 500 million through its maiden international bond issuance via its IFSC Banking Unit at GIFT City, Gujarat. The three-year bonds, maturing in 2029, carry a fixed 5.625% coupon rate and were issued under the Regulation S format to investors outside the US. The notes received an investment-grade BBB- rating from S&P Global Ratings with a stable outlook. Major global investors, including BlackRock and Capital Group, participated in the offering.

Key points:

- IDFC First Bank raised USD 500 million through its IFSC Banking Unit at GIFT City, Gujarat, marking its debut in the global debt capital markets.
- The 3-year bonds, due in 2029, carry a fixed 5.625% coupon rate and an investment-grade 'BBB-' rating from S&P Global Ratings with a stable outlook.
- The bond issue attracted major global institutional investors, including BlackRock, Capital Group, and AllianceBernstein, with interest payments scheduled semi-annually.

10. आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2026, 21 अगस्त को मनाया गया

संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद के पीड़ितों और उत्तरजीवियों को सम्मानित करने तथा उनके उबरने व पुनर्वास में सहायता प्रदान करने के लिए 21 अगस्त 2026 को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। वर्ष 2026 का विषय ₹स्मृति के माध्यम से उपचार₹ था, जिसने ठीक होने की प्रक्रिया में स्मरण के महत्व पर प्रकाश डाला। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2017 में प्रस्ताव ए/आरईएस/72/165 के माध्यम से स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें आतंकवाद के पीड़ितों द्वारा झेले जाने वाले ऑनलाइन नुकसानों से निपटने के लिए एक पहल का शुभारंभ किया गया।

मुख्य बिंदु:

- आतंकवाद के पीड़ितों और उत्तरजीवियों को सम्मानित करने तथा उनके उबरने, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण का समर्थन करने के लिए 21 अगस्त, 2026 को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया।
- वर्ष 2026 का विषय ₹स्मृति के माध्यम से उपचार₹ था, जिसने पीड़ितों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हुए उन्हें याद रखने के महत्व पर जोर दिया।
- संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में आतंकवाद के पीड़ितों के लिए ऑनलाइन नुकसानों को दूर करने और पीड़ितों को फिर से मानसिक आघात से बचाने के लिए ₹आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक सुरक्षित इंटरनेट का निर्माण₹ नामक पहल भी शुरू की गई।

★★★

10. International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism 2026, observed on August 21

The United Nations observed the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism on 21 August 2026 to honour victims and survivors of terrorism and support their recovery and reintegration. The 2026 theme, "Healing Through Memory," highlighted the importance of remembrance in the healing process. The day was established by the UN General Assembly in 2017 through Resolution A/RES/72/165. A high-level virtual event was also held at UN Headquarters, featuring the launch of an initiative to address online harms faced by terrorism victims.

Key points:

- The International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism was observed on August 21, 2026, to honour victims and survivors of terrorism and support their recovery, rehabilitation, and reintegration.
- The 2026 theme, "Healing Through Memory," highlighted the importance of remembering victims while protecting their human rights and fundamental freedoms.
- The UN event also launched the "Building a Safer Internet for Victims of Terrorism" initiative by VoTAN to address online harms and prevent re-traumatisation of victims.

★★★

दैनिक समसामयिक DAILY CURRENT AFFAIRS MCQs प्रश्नोत्तरी

Q1. आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?
(a) 15 अगस्त (b) 20 अगस्त
(c) 21 अगस्त (d) 26 अगस्त

Q2. अगस्त 2026 में IDFC FIRST Bank ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड निर्गम के माध्यम से कितनी राशि जुटाई?
(a) 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर
(b) 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर
(c) 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर
(d) 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर

Q3. किस कंपनी ने अपने PulsePro डेटा को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल में एकीकृत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया?
(a) फोनपे (b) पेटीएम
(c) रेजरपे (d) भारतपे

Q4. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के तहत 5 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा कितने स्कूली शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा?
(a) 40 (b) 45
(c) 48 (d) 50

Q5. कविता संग्रह 'विश्वास दे पृथिवी' के लिए सरला पुरस्कार 2026 हेतु किसे चुना गया है?
(a) गुरु दुर्गा चरण रणबीर
(b) आशुतोष परिदा
(c) दामोदर बेहरा
(d) सीताकांत महापात्र

Q6. स्वदेशी उत्पादन के लिए सबमरीन-फायर्ड डिकॉय की तकनीक किस संगठन ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को हस्तांतरित की है?
(a) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
(b) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
(c) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
(d) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

Q1. On which date is the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism observed every year?
(a) 15 August (b) 20 August
(c) 21 August (d) 26 August

Q2. In August 2026, how much amount did IDFC FIRST Bank raise through its first international bond issuance?
(a) USD 300 million
(b) USD 400 million
(c) USD 500 million
(d) USD 750 million

Q3. Which company signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of Electronics and Information Technology to integrate its PulsePro data into the PM GatiShakti National Master Plan portal?
(a) PhonePe (b) Paytm
(c) Razorpay (d) BharatPe

Q4. How many school teachers will receive the National Teachers' Award 2026 from President Droupadi Murmu on 5 September 2026?
(a) 40 (b) 45
(c) 48 (d) 50

Q5. Who has been selected for the Sarala Award 2026 for the poetry collection 'Bishwas De Prithivi'?
(a) Guru Durga Charan Ranbir
(b) Ashutosh Parida
(c) Damodar Behera
(d) Sitakanta Mahapatra

Q6. Which organization transferred the technology of submarine-fired decoys to Bharat Dynamics Limited for indigenous production?
(a) Indian Space Research Organisation
(b) Defence Research and Development Organisation
(c) Hindustan Aeronautics Limited
(d) Bharat Electronics Limited

Q7. नागरिकों को अवैध गतिविधियों की सीधे रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए हाल ही में चार टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर किस राज्य ने शुरू किए हैं?

(a) ओडिशा

(b) झारखंड

(c) बिहार

(d) पश्चिम बंगाल

Q8. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए अनिवार्य कानूनी अभ्यास की आवश्यकता को तीन वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है?

(a) छह महीने

(b) एक वर्ष

(c) दो वर्ष

(d) अठारह महीने

Q9. 18 अगस्त 2026 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला कौन बनीं?

(a) सोफी एडेनोट

(b) लीया मोरो

(c) क्लाउडी हेगनेरे

(d) सामंथा क्रिस्टोफोरेटी

Q10. केंद्र सरकार ने 2026-27 से 2030-31 तक मोबाइल फोन विनिर्माण योजना के लिए कितना बजटीय परिव्यय निर्धारित किया है?

(a) ₹52,500 करोड़

(b) ₹60,000 करोड़

(c) ₹62,500 करोड़

(d) ₹65,000 करोड़

Q7. Which state recently launched four toll-free helpli ne numbers to enable citizens to directly report illegal activities?

(a) Odisha

(b) Jharkhand

© Bihar

(d) West Bengal

Q8. The Supreme Court reduced the mandatory legal practice requirement for entry-level judicial service examinations from three years to how many years?

(a) Six months

(b) One year

(c) Two years

(d) Eighteen months

Q9. Who became the first French woman to conduct a spacewalk on 18 August 2026?

(a) Sophie Adenot

(b) Léa Moreau

(c) Claudie Haigneré

(d) Samantha Cristoforetti

Q10. What budgetary outlay has the Central Government allocated for the Mobile Phone Manufacturing Scheme for 2026-27 to 2030-31?

(a) ₹52,500 crore

(b) ₹60,000 crore

(c) ₹62,500 crore

(d) ₹65,000 crore

उत्तरमाला (Answer Key)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	A	C	B	B	D	B	A	C

★★★